गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 310 | दि. 11-03-2019 सोमवार | वि.सं. 2075 | फागण सुद -०५ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

११, १८, २३, २९ अप्रैल एवं ६, १२ और १९ मई को चुनाव होंगे

७ चरणों में होगा मतदान, २३ मई को आएंगे नतीजे

८० लोकसभा सीटों वाले युपी, ४० सीटों वाले बिहार, ४२ सीटों वाले प. बंगाल में सभी ७ चरणों में मतदान : चुनावी प्रक्रिया की विडियोग्राफी होगी

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। आयोग ने लोकसभा की कुल ५४३ सीटों पर ७ चरणों में चुनाव का ऐलान किया है। ११, १८, २३, २९ अप्रैल एवं ६, १२ और १९ मई को चुनाव होंगे। सभी चरणों की वोटिंग की गिनती एक साथ २३ मई को होगी यानी १७वीं लोकसभा में सत्ता की चाबी किसके साथ होगी, इसी दिन इसका पता चलेगा। पहले राउंड में २० राज्यों की ९१ सीटों पर मतदान होगा। दूसरे राउंड में १३ राज्यों की ९७ सीटों पर मतदान होगा। तीसरे चरण में १४ राज्यों की ११५ सीटों पर वोट पड़ेंगे। चौथे दौर में ९ राज्यों की ७ सीटों, ५वें में ७ राज्यों की ५१ सीटों, छठे राउंड में ७ राज्यों की ५९ सीटों और ७वें एवं आखिरी दौर में ८ राज्यों की ५९ सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली में छठे चरण में १२ मई को मतदान होगा। सबसे ज्यादा ८० लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश, ४० सीटों वाले बिहार और ४२ सीटों वाले पश्चिम बंगाल में सभी ७ चरणों में मतदान होगा। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड, अंडमान-निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दिल्ली, पुदुचेरी, चंडीगढ़ में एक ही राउंड में मतदान होगा। इस बार सभी पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट मशीनें होंगी। इससे वोटर्स को यह पता चल सकेगा कि उसकी ओर से दिया गया वोट सही उम्मीदवार को ही पड़ा है या नहीं। यही नहीं ईवीएम की भी कई स्तरीय सुरक्षा होगी। हर उम्मीदवार को फॉर्म २६ भरना होगा। देश भर में कुल १० लाख पोलिंग स्टेशनों पर मतदान कराया जाएगा। २०१४ में यह संख्या ९ लाख के करीब थी। सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी होगी। चुनाव प्रचार के लिए ईको-फ्रेंडली सामग्री के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। कोई भी उम्मीदवार अखबार में ३ बार ही विज्ञापन दे सकेगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने PAN कार्ड की जिम्मेदारी नहीं देता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यही नहीं उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए रात १० बजे से सुबह ६ बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर खर्च की गई रकम को भी उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा। सभी उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी भी देनी होगी। इस आम चुनाव में ९० करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। २०१४ से अब तक ८.४ करोड़ मतदाता बढ़े हैं। १.५ करोड़ मतदाता १८ से १९ साल के हैं। बीते चुनाव में ८१ करोड़ वोटर थे। देश के ९९.३ पर्सेंट मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र हैं। १०९५ पर SMS के जरिए लोग मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं। यह नंबर टोल फ्री है। तारीखों के ऐलान के १० दिन बाद वोटिंग लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। हर घर को वोटर गाइड कार्ड दिया जाएगा। सबसे कम लक्षद्वीप में ४९,९२२ वोटर होंगे। सबसे ज्यादा मल्काजगिरी में ३१,८३,३२५ मतदाता है। दिलचस्प तथ्य यह है कि यह पहला ऐसा आम चुनाव है, जब २१वी सदी में जन्मे लोग मतदान कर सकेंगे। २०१४ में हुए आम चुनाव के दौरान इस सदी में जन्मे लोगों की आयु १८ वर्ष नहीं थी, अब इस चुनाव में वे पहली बार देश की सरकार चुनने के लिए वोट डाल सकेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्तसुनील अरोड़ा ने कहा कि दुनिया में करीब ४० लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन पारदर्शिता के मामले में भारत अव्वल देशों में से एक है। पिछले आम चुनावों की बात करें तो २०१४ में ९ चरणों मतदान हुआ था। पहले राउंड की वोटिंग ७ अप्रैल को हुई थी, जबकि १२ मई को आखिरी राउंड की वोटिंग हुई थी। १६ मई को नतीजों का ऐलान हुआ था और २६ मई को नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी।सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में ६ चरणों में मतदान हुआ था। २०१४ में पहली बार इतने ज्यादा चरणों में चुनाव हुआ था, इससे पहले २००९ में ६ और २००४ में ४ चरणों में मतदान हुआ था।

हाइलाइट्स.....

(संपूर्ण समाचार सेवा)नई दिल्ली,

- १७वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का चुनाव ११ अप्रैल, दूसरा चरण १८ अप्रैल, तीसरा चरण २३ अप्रैल, चौथा चरण २९ अप्रैल, पांचवां चरण ६ मई, छठा चरण १२ मई और आखिरी चरण १९ मई को संपन्न कराया जाएगा।
- २३ मई को मतगणना कराई जाएगी।
- पहले चरण में नामांकन की पहली तारीख १८ मार्च होगी और आखिरी तारीख २५ मार्च तय की गई है।
- लोकसभा चुनाव ७ चरणों में संपन्न कराया जाएगा, पहले चरण का चुनाव ११ अप्रैल को होगा।
- लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता तारीखों के ऐलान के साथ लागू हो जाएगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- ९९.३६ % मतदाताओं के पास फोटो वोटर आईडी कार्ड है।
- इस चुनाव में ९० करोड़ वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

CISF स्थापना दिवस पर बोले पीएम मोदी

बहुत हो गया, अब नहीं सहेंगे आतंकवाद : प्रधानमंत्री मोदी

भारत के निर्माण में आपका योगदान अमूल्य है : स्थापना दिवस समारोह के मौके पर सुरक्षाकर्मियों की तारीफ की

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एकबार फिर साफ किया कि वह आतंकवाद के मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बस, अब बहुत हो गया। हम लगातार नुकसान नहीं सकते हैं। पुलवामा और उरी आतंकवादी हमलों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीआईएसएफ के ५०वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर सुरक्षाकर्मियों की खुलकर तारीफ की। सीआईएसएफ को देश और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का आधार बताते हुए पीएम ने कहा कि वैभवशाली भारत के निर्माण में आपका योगदान अमूल्य है। प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ में महिला सुरक्षाकर्मियों की बड़ी भागीदारी को भी देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि वर्दी पहननेवाली बेटियों की संख्या सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा है और मैं बेटियों के साथ उनकी माओं का भी अभिनंदन करता हूं। गाजियाबाद में सीआईएसएफ कैंप में जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, आपके जिम्मे यात्रियों की सुरक्षा है। आपके हाथ में देश के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं। किसी वीआईपी की सुरक्षा देने से कहीं बड़ा आपका काम है। आप अपना काम कितनी मुस्तैदी से निभाते हैं, मैं खुद इसका साक्षी हूं। एक बार मेरे साथ एक बहुत बड़े नेता यात्रा कर रहे थे। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच में कोई छूट नहीं दी गई, वह बेहद नाराज हो गए। फ्लाइट जब लैंड की तो मैंने कहा, मैं आगे चला जाता हूं ताकि पहले मेरी सुरक्षा हो। यह आपकी शक्ति और मुस्तैदी है कि आप सुरक्षा को इतना अहम मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीआईएसएफ के मानवीय कार्यों और शांति काल में अहम भूमिका निभाने की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है। जब विदेशी देशों में आपदा आई तो सीआईएसएफ के जवानों ने जान हथेली पर लेकर मदद की। नेपाल और हैती में हुए भूकंप में आपके राहत कार्यों की सराहना अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी की। जब पड़ोसी मुल्क लड़ने में सक्षम न हो तब वह आतंरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। यह आतंकवाद का दूसरा चेहरा है और ऐसे वक्त में भी आप देश को एकजुट रखने में जुटे रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सुरक्षा बलों के लिए सम्मान जताने की बात कही। उन्होंने कहा, हम अपने सुरक्षा बलों का जितना गौरव बढ़ाएंगे, जितना सम्मान बढ़ाएंगे हमारे देश के लिए उतना अच्छा होगा। एक सामान्य व्यक्ति किसी पुलिसवाले के द्वारा किए गए आचरण से ही पूरी पुलिस फोर्स और सुरक्षा बलों के बारे में राय बना लेता हैं, इसे बदलना बहुत जरूरी है।

आप ने भाजपा मुख्यालय का घेराव किया

दिल्ली सहित देश का भविष्य तय करेगा लोकसभा चुनाव

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

आप ने दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे को आगामी लोकसभा चुनाव का केन्द्रीय मुद्दा बनाते हुये रविवार को यहां भाजपा मुख्यालय का घेराव कर चुनाव अभियान का आगाज किया। इस दौरान आप की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने रविवार शाम को चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की बहुप्रतीक्षित घोषणा किये जाने का हवाला देते हुये कहा कि यह चुनाव दिल्ली सहित पूरे देश के भविष्य को तय करेगा। राय ने कहा कि पार्टी की छात्र इकाई सहित अन्य अनुषांगिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाने के लिये भाजपा और कांग्रेस को समान रूप से जिम्मेदार ठहराते हुये प्रदर्शन किया। राय ने भाजपा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों को पत्र लिख कर उनसे दलों का रुख स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन दोनों का कोई जवाब नही आया। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य की मांग पर आप ने हर संभव प्रयास किए परंतु कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। केंद्र ने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया है इसलिये आप को आंदोलन की तरफ जाना पड़ा।

राम मंदिर पर बोले भैयाजी जोशी

मंदिर बनने तक आंदोलन जारी, केन्द्र सरकार पर कोई संदेह नहीं

मंदिर उसी स्थान पर बनेगा, हम उसके साथ समझौता नहीं करने वाले हैं : मोदी सरकार पर भरोसा जताया

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह भैय्याजी जोशी ने राम मंदिर मुद्दे पर कहा कि यह आंदोलन अभी जारी रहेगा। संघ के वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी की सरकार (केंद्र की बीजेपी सरकार) की निष्ठा पर कोई सवाल नहीं है। उन्होंने मंदिर निर्माण पूरा होने तक आंदोलन के चलते रहने की बात कही। बता दें कि इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर पर मध्यस्थता के लिए ३ सदस्यों का पैनल नियुक्तकिया है। भैयाजी जोशी ने राम मंदिर के लिए मोदी सरकार पर पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि सत्ता में बैठे हुए लोगों में अभी राम मंदिर का विरोध नहीं है। उनकी प्रतिबद्धता को लेकर हमारे मन में कोई शंका नहीं है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले संघ ने एक बार फिर मोदी सरकार पर पूरा भरोसा जताया। अयोध्या विवाद पर मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन सदस्यीय कमिटी के गठन के सवाल पर संघ के सरकार्यवाह जोशी ने कहा, हम किसी भी ऐसे कदम का स्वागत करते हैं। मंदिर उसी स्थान पर बनेगा और हम उसके साथ कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। मध्यस्थ अगर इस दिशा में जाएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। जब तीन सदस्यी पैनल इसपर अपनी कार्यवाही शुरू करेगी तब पता चलेगा। इस प्रकार के सकारात्मक कदम का स्वागत करते है और ऐसी कोशिश होनी चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद के समाधान खोजने के लि ३ सदस्यों वाली मध्यस्थता कमिटी का गठन किया है। कमिटी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एफ. एम. कलीफुल्ला हैं। अन्य दो सदस्यों में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू शामिल हैं। यह संयोग ही है कि मध्यस्थता पैनल में शामिल तीनों ही नाम तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। मंदिर निर्माण तक आंदोलन जारी रखने की बात करते हुए उन्होंने कहा, १९८०-९० से जो आंदोलन चल रहा है, जब तक मंदिर पूरा नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हम न्यायालय से अपेक्षा करते हैं कि शीघ्रता से इस मुद्दे पर फैसला हो। बता दें कि मध्यस्थता के लिए कोर्ट ने ८ सप्ताह का समय तय किया है। कोर्ट की ओर से आध्यात्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर, मध्यस्थता कानूनों के विशेषज्ञ श्रीराम पंचू और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्लाह को मध्यस्थता पैनल के लिए नामित किया गया है।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया

यूपीए के शासनकाल में हुई थीं १२ एयर स्ट्राइक

(संपूर्ण समाचार सेवा) हुबली,

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह के तीन एयर स्ट्राइक के बयान के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) की सरकार के दौरान १२ एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के १० साल के कार्यकाल में १२ एयर स्ट्राइक किए गए थे लेकिन उन्होंने कभी इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया। कलबुर्गी से सांसद खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार शहीदों के शव के साथ खेल रही है। खड़गे हावेरी में पार्टी की रैली को संबोधित करने के बाद हुबली एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास विकास के नाम पर बताने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा, एनएसएसओ की रिपोर्ट के मुताबिक ३८ लाख नौकरियां कम हुईं और २७ लाख नौकरियां पैदा हुईं। लेकिन उन्होंने (बीजेपी) ने लोगों को १० करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था।

संपादकिय

पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर दिखावे की कार्रवाई को लेकर भारत को सतर्क रहना होगा

करतारपुर गलियारे को लेकर अगले हफ्ते शुरू होने वाली बातचीत को द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। एक ऐसे समय जब यह दिखने लगा था कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते तनाव मुक्त होने की दिशा में बढ़ने लगे हैं तब भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि वह पाकिस्तान में आतंकियों की तथाकथित धरपकड़ से संतुष्ट नहीं। आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगाने के हाल के उसके कदम यह बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं करते कि वह आतंकवाद पर सचमुच लगाम लगाने जा रहा है। आखिर यह एक तथ्य है कि पाकिस्तान अपने संरक्षण वाले चुनिंदा आतंकी संगठनों के खिलाफ इस तरह की कागजी कार्रवाई पहले भी कर चुका है। यह भी विचित्र है कि वह जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों पर तो कार्रवाई का दिखावा कर रहा है, लेकिन हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन के खिलाफ दिखावे की भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ध्यान रहे कि बीते दिनों इसी पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन के एक गुर्गे ने जम्मू में विस्फोट किया था। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के कदमों को अपर्याप्त और एक तरह की दिखावे की कार्रवाई करार दिया, लेकिन उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह दुनिया को धोखा न देने पाए। यह एक धोखा ही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री आतंकी संगठन जैश ए मुहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं तो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता यह कहते हैं कि इस नाम का कोई संगठन तो अब अस्तित्व में ही नहीं है। इससे तो यही पता चलता है कि पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में जुट गया है। भारत को इस तरह की चालबाजी को लेकर न केवल खुद सतर्क रहना होगा, बल्कि विश्व समुदाय को भी इसके प्रति आगाह करना होगा कि पाकिस्तान उसे झांसा देने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में पाकिस्तान के प्रति नरमी बरतने वाले चीन सरीखे देशों के रवैये को लेकर कहीं अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। भारत को अमेरिका के रवैये पर भी निगाह रखनी होगी, क्योंकि वह अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश में पाकिस्तान के संरक्षण वाले तालिबान से समझौते की जल्दी में है। तालिबान से जल्दबाजी में किया गया कोई समझौता न केवल अफगानिस्तान को खतरे में डालेगा, बल्कि पाकिस्तान के दुस्साहस को भी बढ़ाएगा। यह ठीक है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया कि करतारपुर गलियारे को लेकर अगले हफ्ते शुरू होने वाली बातचीत को द्विपक्षीय वार्ता की शुरुआत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन इसका अंदेशा तो है ही कि पाकिस्तान इसकी आड़ में उस दबाव से मुक्त होने की कोशिश कर सकता है जो भारत ने बालाकोट हमले के बाद उस पर बनाया हुआ है। निःसंदेह बालाकोट हमले के जरिये भारत ने यह दिखा दिया कि वह सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की क्षमता रखता है, लेकिन अभी यह सुनिश्चित करना शेष है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई की स्थिति में पाकिस्तान पलटवार करने का दुस्साहस न दिखा सके। इस दुस्साहस के दमन के बाद ही पाकिस्तान के सही रास्ते पर चलने की कुछ उम्मीद की जा सकती है।

एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर 'चौकीदार चोर' का अपना नारा

(जी.एन.एस.) जब यह माना जा रहा था कि पाकिस्तान से युद्ध जैसे हालात को देखते हुए राहुल गांधी कुछ दिनों के लिए अपने राफेल राग पर लगाम लगाएंगे तब उन्होंने एक बार फिर राफेल सौदे को लेकर 'चौकीदार चोर' का अपना नारा उछाला। इतना ही नहीं उन्होंने तथ्यों से मुंह चुराते हुए इस सौदे में देरी का आरोप भी मोदी सरकार पर म?दिया, जबकि हर कोई जानता है कि मनमोहन सरकार कैसे वायुसेना की जरूरतों की अनदेखी कर कुंडली मारे बैठी रही। आखिर राहुल का रवैया खुद को जबरन सही साबित करने वाला नहीं तो और क्या है? यह तो कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता है। राफेल पर पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की राय को हिकारत भरी नजरों से देखना भला और क्या है? इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की सरकार ने यही सब तो किया था! 1971 के लोकसभा चुनाव के बाद ही इंदिरा गांधी में यह प्रवृत्ति बलवती होने लगी थी। तब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इंदिरा गांधी एकाधिकारवाद की ओर बड रही हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका का नारा तो आपातकाल से पहले ही दे दिया गया था। इस नारे को कांग्रेसी सांसद शशि भूषण ने उछाला था। कांग्रेस नेतृत्व ने उसका कभी विरोध नहीं किया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब?योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी।

आज की कांग्रेस भी राफेल पर वैसा ही निर्णय चाहती थी जो उसके राजनीतिक विरोधियों के प्रतिकूल पडे, पर जब मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया तो कांग्रेस कह रही है कि हम संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग पर कायम हैं। अब जरा पीछे चलें! 1975 में इंदिरा सरकार ने देश पर आपातकाल थोप दिया। इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता अदालत द्वारा समाप्त कर दिए जाने की प्रतिक्रिया में इतना बडा कदम उठा लिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की अधिसूचना पहले जारी की और मंत्रिमंडल ने उस पर अपनी मुहर बाद में लगाई। यह है इमरजेंसी वाली मानसिकता। याद रहे कि राहुल गांधी ने तो 2013 में उस अध्यादेश की कॉपी को सार्वजनिक रूप से फाड दिया था जिस पर मनमोहन मंत्रिमंडल की मुहर लग चुकी थी। सजायाफ्ता नेताओं को राहत देने के लिए वह अध्यादेश बना था। राहुल के उस कदम के बाद सरकार ने उस अध्यादेश को वापस ले लिया। नतीजतन लालू प्रसाद और रशीद मसूद की लोकसभा की सदस्यता चली गई थी। वैसे तो राहुल का वह काम अच्छा था, पर उनका तरीका इमरजेंसी वाली मानसिकता की उपज लगा। इमरजेंसी में परिवार नियोजन अभियान चला था, पर जिस मनमाने तरीके से चला, उससे बडी आबादी नाराज हो गई। आपातकाल में जयप्रकाश नारायण सहित देश के करीब एक लाख से अधिक विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कर्मियों को जेलों में डाल दिया गया। चूंकि मौलिक अधिकार कौन कहे जीने का अधिकार भी छीन लिया गया था, इसलिए अदालतों को उन गिरफ्तारियों के खिलाफ कोई सुनवाई या कार्रवाई करने से रोक दिया गया था। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों के अनेक बंदियों ने उच्च न्यायालयों में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं दायर कीं। उच्च न्यायालयों ने राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिए। बाद में सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार के पक्ष का समर्थन करते हुए तब सुप्रीम कोर्ट ने बंदियों को कोई राहत नहीं दी। यानी वे बिना किसी कानूनी मदद के लंबे समय तक जेलों में बंद रहे। इसे बनाए रखने में शीर्ष अदालत ने सरकार की जाने–अनजाने बडी सहायता की। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल ख?ा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। यानी एक ही तरह के आरोप से घिरे व्यक्ति को कांग्रेस कैग बनाए तो ठीक, पर यदि दूसरे दल की सरकार बना दे तो गलत। यही है कांग्रेस की आपातकाल वाली मानसिकता! यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि शर्मा या महर्षि के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत थे या सही। यहां तो सिर्फ दोहरे मापदंड की बात हो रही है। इस पृष्ठभूमि में यह बताना प्रासंगिक है कि कैग जैसी संस्था को हमारे संविधान निर्माताओं ने कितनी अधिक गरिमा प्रदान की और साथ ही प्रथम प्रधानमंत्री ने किस तरह उसका पालन किया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कैग के पद को कितना गरिमामय पद मानते थे, उसका एक ही उदाहरण काफी है। प्रथम आम चुनाव का अवसर था। चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री को देशभर में घूमना था। उन्हें विमान की जरूरत थी, क्योंकि यात्राओं के दौरान उन्हें सरकारी काम भी करने थे। विमान के उपयोग का पहले से कोई पूर्व उदाहरण नहीं था। समस्या थी कि इस संबंध में किससे सलाह ली जाए। अफसरों की समिति से या किसी अन्य सेड जवाहरलाल नेहरू ने अफसरों की समिति की जगह कैग से सलाह ली, क्योंकि उनकी नजर में उनको निष्पक्ष माना जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1973 में तीन जजों की वरीयता को नजरअंदाज करके एएन राय को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। एएन राय जनवरी, 1977 तक मुख्य न्यायाधीश रहे। इमरजेंसी को वैधानिक बनाने में उनका ब?ा योगदान था। जस्टिस राय के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में कई निर्णय किए। उनके एक खास निर्णय को तो सुप्रीम कोर्ट ने 42 साल बाद 2017 में पलटा। 1975 का वह एक ऐसा निर्णय था जिसे तत्कालीन केंद्र सरकार ने खूब पसंद किया था। आपातकाल के दमन को जारी रखने में उस निर्णय ने अहम भूमिका निभाई थी। उस निर्णय के जरिये अदालत ने नागरिकों के जीने के अधिकार की सरकार द्वारा समाप्ति पर अपनी मुहर लगा दी थी। आज की कांग्रेस भी यही चाहती है कि राफेल मामले में जब तक कोई अदालत या संस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी नहीं ठहराती तब तक हम उस अदालती या संस्था के निर्णय को नहीं मानेंगे। इसी तरह जब कैग को राफेल डील में कोई घोटाला नहीं मिला तो कांग्रेस ने उसकी निष्पक्षता पर ही सवाल खडा कर दिया। कांग्रेस की ओर से यह भी कहा गया कि खुद अफसर की हैसियत से कैग राजीव महर्षि की संलिप्तता राफेल सौदे में रही थी। मनमोहन सरकार ने 2013 में एसके शर्मा को कैग बनाया तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में शर्मा की नियुक्ति का विरोध किया गया था। आरोप इसी तरह का था जिस तरह का आरोप राजीव महर्षि पर कांग्रेस ने लगाया। सरकार के अफसर तो प्रधानमंत्री के मातहत होते हैं, पर कांग्रेस की मौजूदा पीडी ने राजनीतिक कारणों से संस्था के प्रति जवाहरलाल नेहरू की भावना की भी परवाह नहीं की। उसे तो बस यही चाहिए कि कोई संस्था उस व्यक्ति को राफेल मामले में दोषी ठहरा दे जिसको कांग्रेस दोषी देखना चाहती है। तभी उसे कांग्रेस के उस प्रथम परिवार के समकक्ष मौजूदा प्रधानमंत्री को ला देने में सुविधा होगी। याद रहे कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के प्रथम परिवार के सदस्यों एवं रिश्तेदार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कैग की रिपोर्ट के बाद अच्छा होता कि राहुल राफेल पर दोबारा चर्चा करने से बचते। बहरहाल आपातकाल तथा अन्य अनेक कारणों से इंदिरा गांधी की 1977 के चुनाव में पराजय हुई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। तब लगा था कि कांग्रेस की इमरजेंसी की मानसिकता का खात्मा हो गया, पर कांग्रेस की नई पीडी तो उसे बनाए रखने के पक्ष में लगती है!

जीवनशैली जलवायु परिवर्तन के बडे कारण

(जी.एन.एस.) आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सियोल यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण बात कही कि हमारी जीवनशैली जलवायु परिवर्तन के बडे कारणों में से एक है। यह बात शत–प्रतिशत सही है कि हमने जिस तरह की जीवनशैली अपना रखी है वह एक दिन हम सबको डुबो देगी या फिर हमारा दम घोंट देगी। अगर हम मात्र जीवन की कुछ बुनियादी सुविधाओं तक ही सीमित होते तो भी चलता, पर अत्यधिक पाने की लालसा हमारे लिए एक बडे संकट को जन्म दे रही है। दुर्भाग्य यह है कि हम इस बदलते हालात की चर्चा तो कर रहे हैं, पर इन सुविधाओं को त्यागने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। हर मौसम के बदले से तेवर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं मिली थी? जॉन टेंडल ने वर्ष 1850 में यह बता दिया था कि ग्रीन हाउस गैसें भीषण गर्मी या ठंडी का कारण बन सकती हैं। इसी के आसपास वैज्ञानिकों ने आइसोटोप अध्ययन के आधार पर यह बता दिया था कि बडते कार्बन डाईऑक्साइड का मतलब ज्यादा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग है, लेकिन तब से हम इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही है। जाहिर है जब जलवायु परिवर्तन मानव जनित है तो इसका निदान भी इंसानों के ही हाथों में है। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमश- 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं जो कार्बन उत्सर्जन के खतरे को कम कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमने अपने उपयोगों के लिए भयानक रूप से जंगलों का हनन किया है। वर्ष 2017 में अकेले 390 लाख एकड वनों की कटाई हुई। मतलब एक मिनट में एक पेड काटा गया। यह कटाई हमारी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रही है जिसके विकल्प खोजे जा सकते हैं। मसलन टिंबर के लिए 37 फीसद वनों का हनन होता है, वहीं खेती के लिए 28 फीसद, सडक निर्माण एवं अन्य विकास कार्यों में करीब 140 फीसद। इसके अतिरिक्त 21 फीसद वन दावानल की भेंट चड जाते हैं। यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि मीट और मीट उत्पाद से जुडी हमारी खाद्य आदतें भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बडा कारण हैं। दुर्भाग्य यह भी है कि इनके लिए वर्ष 2030 में आज के मुकाबले 67 फीसद ज्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग होगा। मतलब साफ है आने वाले दिनों में ये इंसानों में संक्रमण का एक बडा कारण बनेंगे। एक आकलन है कि वर्ष 2050 तक सालाना 9.5 मिलियन लोग इसका शिकार बनेंगे। इसके अलावा स्मार्टफोन, निर्माण कार्य एवं कंप्यूटर डाटा जो आज मात्र एक फीसद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का कारण हैं, वर्ष 2040 तक ये 14 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने लगेंगे। अब तमाम अध्ययनों से साफ हो चुका है कि यह जलवायु परिवर्तन मानव जनित है और इसमें मुख्य भूमिका जीवाश्म ईंधनों का बेतहाशा इस्तेमाल, वनों की अंधाधुंध कटाई, अनियोजित शहरीकरण की ही

है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमने प्रकृति के उस व्यवहार से कुछ नहीं सीखा जो यह बताता है कि 'सब कुछ सबके लिए है।' इसी तरह 19वीं शताब्दी के मध्य में आई औद्योगिक क्रांति भी एक लंबे समय से प्रदूषण फैलाने का कारण है। इसके चलते दुनिया के प्रदूषण की चपेट में आने के बाद इसमें भागीदार रहे कई देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए कुछ कदम उठाए। उदाहरण के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने वर्ष 2000 से 2016 के बीच में अपने कार्बन उत्सर्जन में क्रमश- 15 तथा 29 फीसद की कटौती की। सच तो यह है कि यह कटौती उद्योगों पर अंकुश लगा कर नहीं, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को उच्च तकनीकी से कम करने के फलस्वरूप हुई है। इसी तरह आज एरोसॉल, जो कि सूक्ष्म ठोस कण या तरल बूंदों के हवा में मिश्रण होते हैं, एक नए तरह के प्रदूषण हैं। वर्ष 2017 में अकेले अमेरिका ने 2842 मिलियन यूनिट एरोसॉल पैदा किया था। पूरा यूरोप 5666 मिलियन एवं चीन 2123 मिलियन यूनिट एरोसॉल को उत्पादित करते रहे हैं। इसी के साथ दुनिया में तेजी से हो रही जंगलों की कटाई ने भी इस जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया को और गति दी है, क्योंकि ये वन ही हैं यह इसलिए है, क्योंकि हम एक भोगवादी सभ्यता का बडा हिस्सा बन गए हैं। आज दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बडा कारण यातायात है। वर्तमान में विश्व भर में 2 अरब 35 करो? गाडियां सडकों पर हैं और 2035 आते–आते यह संख्या 3 अरब होने वाली है। अब अमेरिका का ही उदाहरण ले लीजिए, जहां यातायात से ही 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जबकि उद्योगों से 22 फीसद, अन्य व्यापार एवं घरेलू उपयोगों से 11 फीसद, खेती से 9 फीसद और बिजली उत्पादों से 28 फीसद ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। ऐसे में यह समझना मुश्किल भी नहीं है कि क्यों यातायात जलवायु परिवर्तन का सबसे बडा कारण है। वास्तव में वहां 76 फीसद लोग अकेले कार में चलते हैं और सार्वजनिक परिवहन मात्र 9 फीसद लोग ही उपयोग में लाते हैं। स्पष्ट है कि अमेरिका की एक बडी आबादी यातायात में बडे पैमाने पर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है। यही हालात कमोबेश भारत के भी हैं जहां वर्ष 2001 से वाहनों की संख्या 5 करोड 50 लाख से बडकर वर्ष 2015 में 21 करोड 24 हजार तक पहुंच गई। हालात ये हैं कि अब सडकें नहीं दिखतीं, बल्कि गाडियां ही दिखती हैं। लिहाजा रोजाना सडकों पर लगने वाला जाम भी कार्बन उत्सर्जन बडाता है। देखा जाए तो यह हमारी जीवनशैली का हिस्सा बन गया है जहां हम स्वतंत्रता महसूस करते हैं। इससे सामूहिकता की भावना के साथ–साथ निर्भरता भी खत्म हुई है। जाहिर है हमें यहां प्रकृति और विज्ञान के नियमों को समझने का समय है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज का जलवायु परिवर्तन हमारी ही देन है। अगर इनसे मुक्त होना है तो हमें ही रास्ते खोजने होंगे। कोई चमत्कार हमें इससे मुक्त नहीं कर सकता। अब जो चर्चा का सबसे बडा विषय होना चाहिए वह यह कि हम अपनी जीवनशैली को ढेर सारी सुविधाओं के दृष्टिकोण से न देखें। संसाधनों का आवश्यकता एवं सुविधा भर उपयोग एक तरफ जहां हमें लंबा जीवन दे सकता है वहीं प्रकृति और पृथ्वी को भी विचलित नहीं करेगा। यह पूरी तरह सच है कि हमारी तेजी से बदलती हुई जीवनशैली ने हमें ऐसे मो? पर पहुंचा दिया है जहां से आगे जीवन दूभर हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम अपने जीने के तौर–तरीकों में सुविधाओं से ज्यादा साधनों के उन तरीकों को अपनाएं जो सततता प्रदान कर सकते हैं।

आरटीओ के पास से शराब-बीयर का जत्था जब्त

लक्जरी बसों में शराब की तस्करी-पार्किंग का बढ़ा आतंक

दिव्यपथ हाईस्कूल रोड पर लक्जरी बसों की अवैध पार्किंग का अड्डा : पुलिस की विफलता को लेकर सवाल

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, अहमदाबाद शहर में लक्जरी बसों में शराब की तस्करी और सार्वजनिक मार्गों पर लक्जरी बसों की अवैध तथा अंधाधुंध पार्किंग का आतंक बढ़ता जा रहा है। फिर भी आरटीओ या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं जाता है, इसे लेकर अब आरटीओ प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर सवाल उठाये जा रहे हैं। शहर के मेमनगर क्षेत्र में एइसी चार रास्ते पहले के ब्रिज नीचे के रास्ते से लेकर दिव्यपथ हाईस्कूल रोड पर तो, लक्जरी बसों और स्कूल बसों की अवैध पार्किंग का जैसे अड्डा हो इस तरह अंधाधुंध और ट्राफिक में आपत्तिजनक लक्जरी पार्किंग की जाती है फिर भी आरटीओ प्रशासन या घाटलोडिया पुलिस या ट्राफिक पुलिस द्वारा कोई कदम उठाया नहीं जाता है। शहर के आरटीओ सर्कल के पास ट्रावेल्स बस की पार्किंग में राजस्थान की बस में से पीसीबी ने १.३० लाख रुपये से ज्यादा शराब-बीयर का जत्था जब्त किए जाने सनसनी मच गई। लक्जरी बसों में शराब की तस्करी के अलावा, जुए के अड्डे, दुष्कर्म सहित की गंभीर प्रवृत्ति के लिए उपयोग हो रहे होने का पहले कई घटनाएं सामने आ चुकी है और इसकी वजह से गंभीर परिणाम आये हैं फिर भी आरटीओ प्रशासन और स्थानीय पुलिस गंभीर लापरवाही बरत रही है। दिव्यपथ हाईस्कूल वाले रोड पर अवैध लक्जरी बसों और स्कूली बसों की पार्किंग सिरदर्द समान बन गई समस्या जैसे ही शहर के चांदलोडिया, चाणक्यपुरी, राणिप, वाडज सहित के क्षेत्रों में भी कुछ ऐसी ही समस्या है फिर भी ट्राफिक पुलिस लक्जरी बसों के लिए स्पेशियल ड्राइव क्यों नहीं चलाती है यह गंभीर सवाल जागरूक नागरिक उठा रहे हैं। शनिवार को सुबह में पीसीबी की टीम को जानकारी मिली थी कि, आरटीओ सर्कक के पास ट्रावेल्स बस की पार्किंग में राजस्थान की बस में शराब लाकर और लोडिंग रिक्शा में अलग-अलग जगहों पर ले जा रहे हैं। जिसके आधार पर पुलिस ने छापेमारी करके ड्राइवर, क्लीनर सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।

कांग्रेस पर पलटवार करते हुए ओम माथुर ने कहा

बीजेपी पर आरोप लगाने के बजाय अपने घर की चिंता करे

लोकसभा निकट आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारियां : लोकसभा सीटों पर समीक्षा की जा रही

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, लोकसभा चुनाव निकट आने के साथ ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा तैयारियां शुरू कर दी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत लोकसभा सीटों पर समीक्षा की जा रही है। गुजरात भाजपा के प्रभारी ओम माथुर शनिवार को राजकोट में है और वह शनिवार को राजकोट की राणींगा वाली में लोकसभा सीट की समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राजकोट भाजपा के कई सीनियर नेता उपस्थित होंगे। राजकोट पहुंचे ओम माथुर ने बताया कि, गुजरात की २६ सीट में से २३ सीट की समीक्षा की गई है जबकि ३ सीट पर की समीक्षा बाकी है जो पूरा किया जाएगा। समीक्षा बैठक का मुद्दा लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल करने का बताया था। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आते नेताओं के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति भाजपा में शामिल हो उसे पार्टी स्वागत करती है ऐसे समय में कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाने के बदले में अपने घर की चिंता करे यह महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तब गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जूनागढ़ के कांग्रेस के विधायक जवाहर चावडा ने शुक्रवार को इस्तीफा देने के बाद शाम को भाजपा में शामिल हो गए। जवाहर चावडा को अब वर्तमान रुपाणी सरकार मंत्री पद देने जा रही है। जवाहर चावडा सरकार में मंत्री बनेंगे और रविवार दोपहर में १२.३९ बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के नेता भरतसिंह सोलंकी शुक्रवार को वडोदरा में कांग्रेस दफ्तर पहुंचे और पत्रकारों के साथ बात की। समीक्षा बैठक का मुद्दा लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बढ़त हासिल करने का बताया था। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आते नेताओं के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति भाजपा में शामिल हो उसे पार्टी स्वागत करती है ऐसे समय में कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाने के बदले में अपने घर की चिंता करे यह महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ तब गुजरात की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जूनागढ़ के कांग्रेस के विधायक जवाहर चावडा ने शुक्रवार को इस्तीफा देने के बाद शाम को भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने पत्रकारों के साथ बात करते हुए कहा कि, जवाहर चावडा अपने निजी लाभ चाहिए भाजपा में गये है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कि, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी घोटालेबाज पार्टी है। भाजपा के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिए गुजरात की २६ सीटों के उम्मीदवार नहीं है इसी वजह से कांग्रेस के विधायकों को लालच देकर भाजपा में शामिल कर रहे हैं।

छबील का बेटा सिद्धार्थ पटेल सीट के समक्ष पेश

भानूशाली : आखिर में छबील का बेटा सिद्धार्थ की पूछताछ

सीट के अधिकारियों ने बंददरवाजे में छबील के बेटे की घंटों तक पूछताछ की : केस में महत्व की जानकारियां

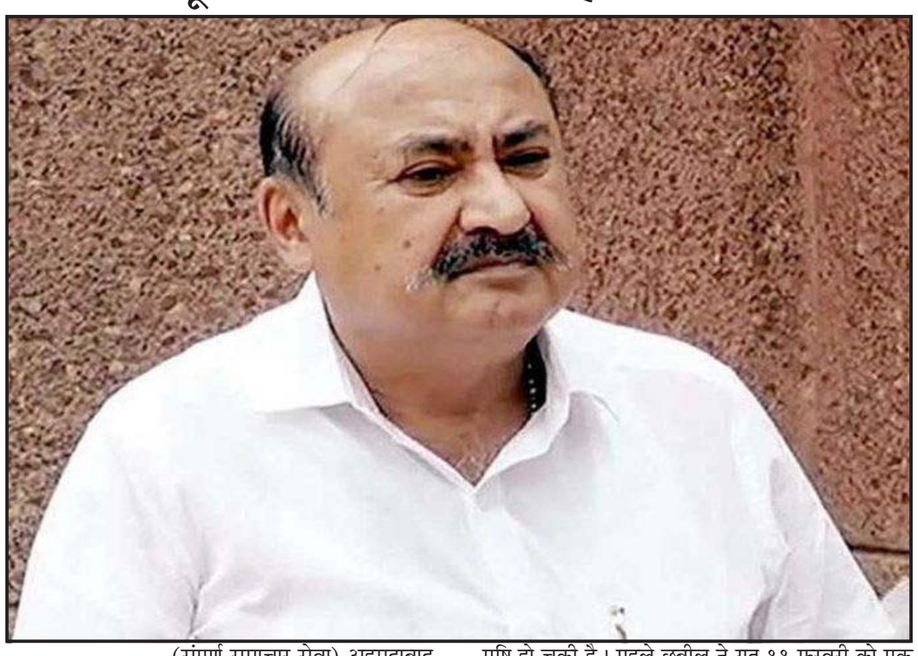

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, भाजपा के नेता जयंती भानूशाली की हत्या के आरोपी छबील पटेल का बेटा सिद्धार्थ पटेल शनिवार को जांच एजेंसी स्पेशियल इन्वेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश हुए। सीट के अधिकारियों द्वारा छबील पटेल के बेटे की बंददरवाजे में घंटों तक पूछताछ की गई। सूत्रों के अनुसार, छबील का बेटा सिद्धार्थ ने अधिकतर प्रश्नों का योग्य जबाव नहीं दिया लेकिन सीट के अधिकारियों ने केस में मददरूप हो ऐसी कई जानकारियां जानने को मिली है, जिसके आधार पर अब सीट की तरफ से केस में आगामी जांच में प्रगति की जाएगी। गुजरातभर में सनसनी मचाने वाले जयंती भानूशाली हत्या केस में अभी तक में आरोपी राहुल पटेल, नीतिन पटेल, शशीकांत कांबले, अशरफ अनवर शेख और विशाल कांबले की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिसमें से विशाल कांबले की रिमांड पूरा होने पर इसे पूना की यरवडा जेल में भेज दिया गया। उल्लेखनीय है कि, जयंती भानूशाली हत्या केस में छबील पटेल फरार चल रहे हैं और वह विदेश में होने की पुष्टि हो चुकी है। पहले छबील ने गत ११ फरवरी को एक ऑडियो वायरल किया था और बताया कि, फिलहाल मैं बिजनेस के लिए विदेश आया हूं। काम के लिए अक्सर विदेश जाना होता है। विदेश आने के बाद मुझे जानकारी मिली कि मेरे खिलाफ पुलिस शिकायत हुई है तो मैं मीटिंगों को पूरा करके तुरंत भारत आकर पुलिस स्टेशन पर पेश हो जाऊंगा। मैं निर्दोष हूं और किसी साजिश का शिकार बन रहा हूं ऐसा मुझे लगता है। मुझे गुजरात की पुलिस पर पूरा विश्वास है। अंतिम मीटिंग पूरा करके मेरे आने की तारीख भी पहले से ही दूंगा। मेरा काम पूरा होने की तैयारी में है। हालांकि, छबील पटेल के यह विडियो वायरल होने के बाद भानूशाली के परिजनों ने यह छबील पटेल का एक स्टंट सिर्फ होने का और पूरी साजिश इसके इशारे पर किए जाने का और यह मुख्य सुत्रधार आरोपी होने का गंभीर आरोप फिर एक बार लगाया था। हालांकि, सीट द्वारा पूरे मामले की जांच के लिए छबील पटेल का बेटा सिद्धार्थ को बुलाकर इसकी घंटों तक पूछताछ की गई थी।

योगेश, चावडा और हकुभा ने मंत्री के तहत शपथ

सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार : और ३ मंत्री शामिल

कांग्रेस से आये चावडा को कैबिनेट मंत्री के तौर पर स्थान दिया : सहकारी खाता दिए जाने की संभावना है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, आज गुजरात की राजनीति में काफी उतार-चढाव बाद रुपाणी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। गांधीनगर के राजभवन में विजय मूहुर्त में शनिवार को भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिसमें योगेश पटेल, धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा (हकुभा जाडेजा) और जवाहर चावडा ने मंत्री पद के तहत शपथ लिया। राज्यपाल ओपी. कोहली ने नए तीन मंत्रियों को पद और गोपनीयता के शपथ दिलाये। अब चावडा को सहकारी खाता की जिम्मेदारी दिए जाने की संभावना है। तीन नए मंत्रियों ने मंत्रीपद की शपथ लेने के बाद उनके कार्यों और जनसेवा करने का उद्देश्य व्यक्त किया। शनिवार को शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर राजेन्द्र त्रिवेदी, राज्य के सीएम विजय रुपाणी और डेप्यूटी सीएम नीतिन पटेल उपस्थित हुए। सभी तीन मंत्रियों को राज्यपाल ओपी. कोहली ने शपथ दिलाया। जवाहर चावडा बाद राज्यपाल ओपी. कोहली ने योगेश पटेल को मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। योगेश पटेल ने राज्यस्तर के मंत्री के तौर पर शपथ लिया। इसके अलावा धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा ने भी मंत्री के तौर पर शपथ ली। नीतिन पटेल ने शपथ ग्रहण कार्यक्रम बाद बताया कि, विजय रुपाणी के मंत्रिमंडल में और तीन मंत्री शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री के तौर पर जवाहर चावडा और राज्यस्तर के मंत्री के तौर पर धर्मेन्द्रसिंह जाडेजा और योगेश पटेल ने शपथ लिया। अभी तक उनको विभाग का आवंटन नहीं कराया गया है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की असर गांधीनगर में हुई है। नीतिन पटेल शनिवार को पहली बार पाकिस्तान के विरूद्ध हमले की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के यह तीन मंत्री पीएम मोदी की राष्ट्रभक्ति की वजह से भाजपा में शामिल हुए हैं। देशभर के जैसे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, यह आज गुजरात में भी लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। नीतिन पटेल ने अपनी बात करते हुए कहा कि, नेता हो तो मोदी जैसा होना चाहिए कहकर भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं।

पुलिस ने एक महिला सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

हाटकेश्वर क्षेत्र से अवैध कॉल सेंटर पकड़े जाने से सनसनी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, शहर के हाटकेश्वर क्षेत्र से अमेरिका के नागरिकों के साथ लोन, वेरिफिकेशन सहित के बहाने के तहत धोखाधड़ी करके लाखों रुपये वसूलने का अवैध कॉल सेंटर पकड़े जाने से पूरे क्षेत्र में सनसनी मच गई। खोखरा पुलिस ने यह पूरे मामले में एक महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कॉल सेंटर में लोन और वेरिफिकेशन के बहाने फोन करके आरोपियों ने धोखाधड़ी कर रहे होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज करके उनके पास से तीन लेपटोप, कंप्यूटर, मैजिक जेक सहित का मालसामान जब्त किया गया। अहमदाबाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी करके अवैध कॉल सेंटर जब्त करने का सिलसिला कई लंबे समय से चल रहा है लेकिन अपराधियों को पुलिस की यह कार्रवाई और समाचार माध्यमों में इसे पर्दाफाश करने की घटना मालूम होने के बावजूद भी अवैध कॉल सेंटर की क्राइम प्रवृत्ति चलाने से बाज नहीं आते है। ऐसी ही एक घटना में शहर के हाटकेश्वर क्षेत्र से और एक अवैध कॉल सेंटर पकड़ा गया। खोखरा पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर हाटकेश्वर क्षेत्र में भाग्योदयनगर में स्थित एक मकान में छापेमारी करके अवैध कॉल सेंटर चला रहे विनय मकवाणा, हिरेन देसाई और सूचिता शुक्ला की गिरफ्तारी की गई। आरोपियों ने मैजिक जेक डिवाइस द्वारा वह अमेरिका के नागरिकों को कॉल करते थे और उनको लोन देने की लालच देकर वेरिफिकेशन फीस, एग्रीमेन्ट फीस के बहाने पैसे वसूलते थे। कॉल सेंटर में लोन और वेरिफिकेशन के बहाने फोन करके आरोपियों ने धोखाधड़ी कर रहे होने की प्राथमिक जानकारी सामने आई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज करके उनके पास से तीन लेपटोप, कंप्यूटर, मैजिक जेक सहित का मालसामान जब्त किया गया।डोलर आइटयून्स के द्वारा तथा मनीग्राम द्वारा वह पैसे लेते थे। पुलिस ने घटनास्थल से छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से ३ लेपटोप, ३ कंप्यूटर सेट, मैजिक जेक, १० डेबिट कार्ड सहित के मालसामान को जब्त किया गया और पूरे मामले में जरूरी अपराध करके आगे की जांच शुरू कर दी है।

सब की नजरे राजामौली की RRR पर टिकी हैं

आलिया ने ठुकराई बाहुबली फिल्म डायरेक्टर की फिल्म

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, सिनेमा जगत की सबसे हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल बाहुबली की सफलता के बाद हर किसी की नजरें बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली की आने वाली फिल्म RRR पर टिकी हैं। डायरेक्टर ने अपनी आने वाले फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो जहां मेल लीड रोल में रामचरण तेजा और जूनियर एनटी रामाराव दिखेंगे। वहीं फीमेल लीड रोल के लिए अभी कोई ऐक्ट्रेस को नहीं चुना गया है। इस फिल्म की कहानी से लेकर रिलीज डेट और लीड ऐक्ट्रेस के रोल को लेकर काफी चर्चाएं हैं। खबरें थीं कि इस फिल्म में महिला का लीड रोल के लिए डायरेक्टर ने पहले परिणिती चोपड़ा और आलिया भट्ट को ऑफर किया था। बाद में ऐसी भी खबरें थीं कि फिल्म के लिए फी पर सहमति नहीं बनने के कारण बात आगे नहीं बढ़ी। अब नई रिपोर्ट से पता चला है कि फिल्म के डायरेक्टर राजामौली आलिया भट्ट को भारी भरकम फी चुकाने के लिए सहमत हो गए थे। यहां तक कि उन्होंने करण जौहर के जरिए आलिया से संपर्क भी कर लिया था। बाद में आलिया भट्ट ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हए फिल्म में काम करने से मना कर दिया। मालूम हो, फिलहाल आलिया अपनी आने वाली फिल्म कलंक को लेकर बिजी हैं जो १७ अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्म में वह रूप के किरदार में नजर आएंगी। इसके साथ ही वह ब्रह्मस्त्र की शूटिंग भी कर रही हैं और जल्द ही इस साल के अंत में करण जौहर की आने वाली फिल्म तख्त की शूटिंग भी शुरू करने वाली हैं। इससे पहले वह राजी और गली बॉय में अपनी ऐक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं।

अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपने बिजी शेड्यूल का हवाला देते हए फिल्म में काम करने से मना कर दिया

प्रॉपर्टी कार्ड और टेनामेंट नंबर सहित का लिंक अप

सर्वे आधारित संपत्तियों को टेनामेंट के साथ जोड़ा जाएगा

सीटी सर्वे की ऑफिस-एएमसी के कर्मचारी संयुक्त रूप से पूरा कामकाज कर रहे : प्रॉपर्टी की जानकारी ऑनलाइन

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, राज्य सरकार की सूचना से इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत शहर सहित राज्यभर में प्रॉपर्टी कार्ड (संपत्ति कार्ड) संबंधित संपत्ति की जंत्री, बिक्री दस्तावेज, हक-दावा तथा प्रॉपर्टी टैक्स के बोझ सहित की विस्तृत जानकारी के साथ लिंक करने के काम किया जा रहा है। यह लिंक अप की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रॉपर्टीकार्ड धारक विदेश में बैठे बैठे संबंधित प्रॉपर्टी की जंत्री बिक्री दस्तावेज, अधिकार -दावा तथा प्रॉपर्टी टैक्स के बोझ की जानकारी को राज्य के राजस्व विभाग की वेबसाइट ई.मिलकत गुजरात.गव.इन पर ऑनलाइन मालूम किया जा सकेगा। इसकी वजह से प्रॉपर्टी की बिक्री या खरीदी बाद के विवाद में कमी होगी। फिलहाल में म्युनिसिपल कमिशनर विजय नेहरा ने ऑफिस ऑर्डर जारी करके राज्य सरकार के इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत सीटी सर्वे विभाग के प्रॉपर्टीकार्ड की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रॉपर्टी टैक्स के टेनामेंट नंबर के साथ जोड़ने के लिए टैक्स विभाग के ५० से ज्यादा कर्मचारियों को लगाया गया है।

शहर की सीटी सर्वे सुपरिन्टेन्डेन्ट -एक दो और तीन ऑफिस के तहत सिटी सर्वे वोर्ड के सिटी सर्वे विभाग के कर्मचारी के साथ म्युनिसिपल टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने संबंधित क्षेत्र में सर्वे करके प्रॉपर्टी कार्ड और टेनामेंट नंबर लेकर इसे नोट किया जाएगा। इसके लिए दोनों विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जल्दी से कामकाज शुरू किया गया है। फिलहाल में जिला कलेक्टर और म्युनिसिपल कमिशनर की दो बार संयुक्त मीटिंग आयोजित की गई आगामी १० मार्च तक में प्रॉपर्टी कार्ड के साथ टेनामेंट नंबर लिंकिंग का काम पूरा करना होगा, हालांकि शहर में २.७२ लाख प्रॉपर्टी कार्ड को म्युनिसिपल प्रशासन के चोपडे में दर्ज हुई १८ लाख प्रॉपर्टी के साथ लिंक करने की वजह से यह काम अभी देरी से किया जाएगा। जिस म्युनिसिपल क्षेत्र में सिटी सर्वे नंबर नहीं है ऐसे क्षेत्र में ७/१२ की जानकारी आधारित कामकाज किया जा रहा है।

अमेरिकन नागरिकों को लोन सहित के बहाने के तहत फंसाकर लाखों रुपये वसूलने का और एक घोटाला

आज भी एक हजार से ज्यादा लोग खुले में शौच करते है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, एचडीआरसी, अहमदाबाद द्वारा शहर के २४ स्लम क्षेत्र के ७५१२ परिवारों के प्रतिनिधिरूप १४२ व्यक्तियों का एक अनौपचारिक महत्व का सर्वे शुरू किया गया। जिसमें चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई कि, अहमदाबाद में आज भी एक हजार से ज्यादा लोग खुले में शौच करने के लिए मजबूर है। उचित मूल्य की दुकानों में नियम के अनुसार अनाज गरीब वर्ग को नहीं मिलता है। बारकोड में अंगूठे के निशान के लिए पांच रुपये लिए जाते होने की चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई है। यह सर्वे में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस), खुले में शौच करने और शहर के विकास के लिए स्थल पर से हटाकर अन्य जगह पर पुनर्वास पाये लोग की हाल की स्थिति को शामिल किया गया। अहमदाबाद शहर के २४ स्लम क्षेत्र की स्थिति का एचडीआरसी द्वारा शुरू किए गए महत्व के सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई मामले में संस्था के फिल्ड कॉ-ऑर्डिनेटर दीपक सोलंकी, प्रॉजेक्ट मैनेजर शहेनाज अन्सारी और फिल्ड वर्कर भावनाबहन ने बताया कि, शहर के सर्वे में शामिल क्षेत्र में आज भी १७९५ परिवारों को खाद्य आपूर्ति नियंत्रण कार्यालय के तहत उचित मूल्य की दुकानों में नीति-नियम के अनुसार, अनाज नहीं मिलता है। ५११६ परिवारों एपीएल राशनकार्ड होने से अनाज नहीं मिलता है। १४२ परिवारों से हर महीने के आखिर में सस्ते अनाज की दुकान में बारकोड सिस्टम में अंगूठे के निशान लगाते समय दुकानदार द्वारा पांच रुपया लिया जाता है और इसकी कोई स्लीप नहीं दी जाती है यह बहुत ही गंभीर जानकारी सामने आई थी। सर्वे में दूसरी जो चौंकाने वाली और सनसनी मचाने वाली बात सामने आई थी कि गुजरात सरकार ओपन डेफेक्शन गुजरात की बात कर रही है। स्वच्छता मामले में अभी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पुरस्कार भी मिला है लेकिन वास्तविकता यह है कि, अहमदाबाद शहर में आज भी १०३० लोग खुले में शौच कर रहे हैं।

सीबीआई ने इंटरपोल और यूके सरकार से मांग की

CBI ने नीरव मोदी को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की

सीबीआई इंटरपोल यूके से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहेंगे कि नीरव मोदी वहां से कहीं और न जाए

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

लंदन की सड़कों पर भगोड़े नीरव मोदी के दिखने के बाद, भारतीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। सीबीआई ने इंटरपोल और यूके अथॉरिटीज से सम्पर्क साधकर भगोड़े कारोबारी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि वह इंटरपोल यूके से बात कर यह सुनिश्चित करने को कहेंगे कि नीरव मोदी वहां से कहीं और न जाए। माना जा रहा है कि नीरव मोदी किसी अन्य देश भागने की फिराक में है। अधिकारियों का कहना है कि यूके की अथॉरिटी और इंटरपोल ने उन्हें अगस्त २०१८ में बताया था कि नीरव मोदी उनके देश में है, लेकिन उसकी सही लोकेशन की जानकारी नहीं है। भारतीय एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि नीरव मोदी यूरोपियन देशों में काफी यात्रा कर रहा है और भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में अपने खिलाफ चल रही प्रक्रियाओं के संबंध में वकीलों से मिलता है। पिछले साल वह जिन देशों में यात्रा करके आया है, उनमें फ्रांस, हॉन्गकॉन्ग, अमेरिका और बेल्जियम है। एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, 'क्योंकि अब हमें नीरव मोदी की लोकेशन पता है, ऐसे में सबसे पहला कदम उसे गिरफ्तार करने का होना चाहिए। क्योंकि उसके खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले हैं, जिनकी जानकारी यूके सरकार को प्रत्यर्पण की मांग में दी गई है। क्योंकि उसका भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया गया है, ऐसे में यूके सरकार को यह भी देखना चाहिए किन डॉक्युमेंट्स के आधार पर यात्रा कर रहा है। जैसे ही नीरव मोदी को गिरफ्तार किया जाएगा, सीबीआई और ईडी की जॉइंट टीम को लंदन रवाना किया जाएगा, जो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। जुलाई में ही नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरनैशनल अरेस्ट वॉरंट जारी किया गया था, जबकि यूके की सरकार से प्रत्यर्पण की मांग पिछले साल अगस्त में की गई थी।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान

एफ-१६ को गिराने का भारत का दावा पूरी तरह निराधार

(संपूर्ण समाचार सेवा) इस्लामाबाद,

पाकिस्तान ने भारत के उस दावे को पूरी तरह निराधार बताकर खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि हाल में हुई हवाई झड़प के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के एक एफ-१६ लड़ाकू विमान को मार गिराया था। पाकिस्तान ने कहा कि घरेलू राजनीतिक फायदे को ध्यान में रखकर भारतीय सरकार लगातार लोगों को भ्रमित कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शनिवार को नयी दिल्ली में मीडिया को बताया गया था कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान द्वारा उड़ाए जा रहे भारतीय वायुसेना के मिग-२१ बाइसन विमान ने पाकिस्तान के एक एफ-१६ लड़ाकू विमान को मार गिराया था और इस बात के प्रत्यक्षदर्शी गवाह और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी हैं। कुमार के इस बयान के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का यह बयान आया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय (एफओ) ने शनिवार देर शाम कहा, भारत सरकार और भारतीय मीडिया घरेलू राजनीतिक फायदे और अपनी विफलताओं और उसके बाद की शर्मिंदगी से बचने के लिये अंतरराष्ट्रीय समुदाय और भारतीय लोगों को भ्रमित करने के लिये लगातार गलत जानकारी फैला रहा है। इसमें कहा गया, ''एक भारतीय विमान के पाकिस्तानी एफ-१६ को मार गिराने के झूठे दावे पूरी तरह निराधार हैं और इनका मकसद सिर्फ भारतीय लोगों को संतुष्ट करना था लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने एक के बाद एक झूठ उजागर कर दिया। भारत ने शनिवार को यह भी कहा था कि उसने अमेरिका से इस बात की जांच के लिये भी कहा है कि क्या भारत के खिलाफ एफ-१६ का इस्तेमाल इस्लामाबाद को बेचे गए लड़ाकू विमानों की शर्तों के मुताबिक है। बयान में पुलवामा आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद का हाथ होने के भारत के रुख को भी खारिज करते हुए कहा गया, स्थानीय विस्फोटकों और गाड़ियों के इस्तेमाल समेत स्वदेशी मूल और नियंत्रण रेखा से कई मील की दूरी से भारत के दावों का कोई तुक नहीं बनता। इसमें कहा गया कि आत्मघाती हमले के संदर्भ में भारत से भेजे गए डॉजियर की जांच की जा रही है।

चुनाव के ऐलान से पहले अखिलेश का हमला

परिवर्तन का रुझान है, जनता बहुत परेशान है : अखिलेश

बीजेपी के लोग सत्ता में आने के लिए किसी भी सीमा में जा सकते हैं : बीजेपी झूठ बोलने वाली सरकार है

(संपूर्ण समाचार सेवा) लखनऊ,

लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ जमकर हमला बोला। वहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले उन्हें बताया जाए कि यह अफवाह किसने फैलाई है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के लिए किसी भी सीमा में जा सकते हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने लखनऊ में लूटकांड को लेकर डीजीपी ओपी सिंह को हटाने की मांग की। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अखिलेश ने कहा, परिवर्तन का रुझान है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। अखिलेश ने इस दौरान कहा, बीजेपी झूठ बोलने वाली सरकार है। वह कुछ भी कर सकती है। एसपी अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी ने अपना प्रचार करने के लिए उर्दू का सहारा लिया। उन्होंने बीजेपी के कैपेन मोदी है तो मुमकिन है पर सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी को इतनी नफरत है तो मुमकिन है शब्द हटाए। एसपी-बीएसपी गठबंधन में सीटों पर कथित अनबन को लेकर उन्होंने कहा, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अब जनता में जाकर अपील करने का वक्त है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने कितना परेशान किया है व्यापारियों को। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम मोबाइल बना रहे हैं सब चीन से मोबाइल मंगा लिए। ये धोखा जनता को न दें। लखनऊ में पुलिस द्वारा कारोबारी को गन पॉइंट पर लेकर डकैती डालने के मामले में अखिलेश ने डीजीपी ओपी सिंह को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब पुलिस ही चोरी कर रही है। कितनी शर्म की बात है। सरकार को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भी मायावती की तरह डीजीपी ओपी सिंह से इस्तीफे की मांग करते हैं।

ओडिशा : CM नवीन पटनायक का ऐलान

लोकसभा चुनाव में ३३% टिकट महिलाओं को देंगे

नवीन पटनायक इससे पहले संसद और विधानसभा में भी महिलाओं के आरक्षण की पैरवी करते रहे हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा) भुवनेश्वर,

ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल (बीजेडी) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। एक रैली के दौरान सीएम पटनायक ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महिला उम्मीदवारों को टिकट आवंटन में ३३% आरक्षण देगी। गौरतलब है कि पटनायक इससे पहले संसद और विधानसभा में भी महिलाओं के आरक्षण की पैरवी करते रहे हैं। पटनायक केंद्रपाड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ऐलान किया कि बीजेडी आगामी लोकसभा चुनाव में टिकट आवंटन में महिलाओं को ३३% आरक्षण देगी। उन्होंने बाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मुझे आज केंद्रपाड़ा आकर बेहद खुशी हो रही है। गौरतलब है कि पटनायक इससे पहले राज्य विधानसभा में संसद और विधानसभा में महिलाओं को ३३% आरक्षण देने का प्रस्ताव रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ओडिशा को लेकर यह समर्पण दिखाना चाहिए कि यहां महिलाएं सशक्तहैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने रविवार शाम पांच बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनावों के साथ ही ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी कराए जाएंगे, क्योंकि राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है।

गुजरात कांग्रेस विधानसभा के सदस्य अल्पेश ठाकोर ने अपने आवास पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। जिसमें कई जानकारियां दी गई। (संपूर्ण समाचार सेवा)

हमले में २७ सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी

पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे : ईरान

ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कर कार्रवाई करने की मांग की

(संपूर्ण समाचार सेवा) तेहरान,

ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को फोन कर आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की मांग की है। रूहानी ने यह मांग बीते महीने ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हुए हमले के संदर्भ में कही है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान के एक आत्मघाती हमलावार ने ही सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हमले को अंजाम दिया था। उस हमले में २७ सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई थी। सुन्नी जिहादी समूह जैश-अल-अद्ल ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ईरान का मानना है कि यह समूह पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी गतिविधियां चलाता है। ईरान ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी पर जिहादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है तथा हमले के मद्देनजर देश के राजदूत को तलब किया। हसन रूहानी ने शनिवार शाम इमरान खान से फोन पर बात की तथा रिश्ते बेहतर बनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने तेहरान के पारंपरिक क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय दुश्मनों पर भी उंगली उठाई। ईरान सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक रूहानी ने कहा, हमें जिहादी समूहों की वजह से दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती तथा भाईचारे को प्रभावित नहीं होने देना चाहिये। दोनों देश जानते हैं कि उन्हें हथियार और वित्तीय मदद कहां से मिल रही है। ईरान के राष्ट्रपति का इशारा अमेरिका, इजराइल के साथ-साथ सऊदी अरब तथा संयुक्तअरब अमीरात की ओर था। सुन्नी जिहादी समूह जैश-अल-अद्ल ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ईरान का मानना है कि यह समूह पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी गतिविधियां चलाता है। ईरान ने पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी पर जिहादियों को पनाह देने का आरोप लगाया है तथा हमले के मद्देनजर देश के राजदूत को तलब किया। हसन रूहानी ने शनिवार शाम इमरान खान से फोन पर बात की तथा रिश्ते बेहतर बनाने की अपील की।ईरान का आरोप है कि ये देश पाकिस्तान की धरती पर मौजूद जिहादी समूहों को मदद पहुंचाते है।

राणिप पुलिस स्टेशन क्षेत्र में बस से शराब का जत्था का मिला।

पाकिस्तान ने एफएटीएफ से हटाने की मांग की

एफएटीएफ समीक्षा इकाई से भारत को हटाने की मांग की

पाकिस्तान का कहना है कि भारत के सह अध्यक्ष रहते पाकिस्तान को लेकर निष्पक्ष समीक्षा नहीं हो सकती है

(संपूर्ण समाचार सेवा) इस्लामाबाद,

पुलवामा आतंकी हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े प्रहार जारी रखने के बयान के बाद पाकिस्तान डर गया है। पुलवामा का बदला लेने के लिए भारत ने बालाकोट में जैश के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर उसे ध्वस्त कर दिया था। अब पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के वित्तपोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनैंशल ऐक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) से अनुरोध किया है कि भारत को संस्था के एशिया प्रशांत संयुक्तसमूह के सह अध्यक्ष पद से हटाया जाए। पाकिस्तान का कहना है कि भारत के सह अध्यक्ष रहते पाकिस्तान को लेकर निष्पक्ष समीक्षा नहीं हो सकती है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर ने पेरिस स्थित संस्था एफएटीएफ के अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसलीआ को भेजे एक पत्र में भारत के अलावा किसी अन्य सदस्य देश को एशिया पेसिफिक जॉइंट ग्रुप का सह अध्यक्ष नियुक्तकरने के लिए कहा है ताकि एफएटीएफ की समीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ हो। उमर ने पत्र में लिखा है, पाकिस्तान के प्रति भारत का द्वेष भाव जगजाहिर है और हाल में पाकिस्तान के वायु क्षेत्र का उल्लंघन और पाकिस्तानी क्षेत्र में बम गिराया जाना भारत के शत्रुतापूर्ण रवैया का एक और उदाहरण है। पाकिस्तान एशिया पसिफिक ग्रुप का सदस्य है। एफएटीएफ के सामने एपीजी ने ही पाकिस्तान का पक्ष रखा है। भारत के फाइनैंशन इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर जनरल इस ग्रुप के सह अध्यक्ष हैं। उमर ने अपने पत्र में लिखा है, पाकिस्तान के प्रति भारत का रवैया काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा है और हाल ही में भारत ने पाक के वायु सीमा का उल्लंघन करके बम फेंके थे। पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने का जिक्र करते हुए उमर ने कहा, भारत के इस समूह का सह अध्यक्ष होने ने से रिव्यू प्रक्रिया का निष्पक्षता से होना मुश्किल है। हमारा मानना है कि भारत पाक के प्रति जायज रवैया नहीं दिखाएगा। १८-२२ फरवरी को हुई समीक्षा बैठक के दौरान एफएटीएफ ने पाया कि जनवरी २०१९ तक पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई में बेहद कम बढ़ोतरी की है। पाकिस्तान की कार्रवाई पर असंतुष्टि जताते हुए एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की है।

नौरोबी जा रहा इथोपिया का विमान

इथोपिया का विमान क्रैश हुआ, १५७ यात्रियों की मौत

(संपूर्ण समाचार सेवा) नैरोबी,

इथोपिया के अदिस अबाबा से नैरोबी जा रही इथोपियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट उड़ान भरने के ६ मिनट के अंदर ही क्रैश हो गई जिसमें सभी १५७ लोगों को मौत हो गई। मृतकों में१४९ पैसेंजर्स और ८ क्रू मेंबर्स शामिल थे। इथोपिया के प्रधानमंत्री ने विमान हादसे की पुष्टि की है। इथोपिया एयरलाइंस का यह विमान स्थानीय समय से सुबह ८.३८ मिनट पर अदिस अबाबा से उड़ान भरा था और सुबह करीब ८.४४ मिनट पर उसका संपर्क टूट गया। राहत और बचाव अभियान जारी है। फ्लाइट ईटी ३०२ राजधानी अडिस से करीब ६० किलोमीटर दूर बिशोफ्टु शही में यह हादसा हुआ है। एयरलाइन ने बताया कि जिस प्लेन में हादसा हुआ है वह ७३७-८०० मैक्स था। इथोपिया के पीएम ने ट्वीटर पर इस हादसे को लेकर दुख जताया है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH